भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 540

06 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

आईएसए स्टील कॉन्क्लेव 2023

540. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आईएसए स्टील कॉन्क्लेव 2023 के चौथे संस्करण में देश में क्षमताओं में वृद्धि करने पर जोर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत ने पिछले दशक में व्यापक वृद्धि दर्ज की है और यह कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा देश में और अधिक इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क): भारतीय इस्पात संघ (आईएसए) द्वारा 'आईएसए स्टील कॉन्क्लेव 2023' के चौथे संस्करण का आयोजन 7-8 नवंबर, 2023 के दौरान नई दिल्ली में किया गया था। आईएसए एक स्वतंत्र औद्योगिक निकाय है जो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के इस्पात उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है। इस कॉन्क्लेव में हितधारकों द्वारा इस्पात उद्योग से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चाएं की गईं। यह कॉन्क्लेव एक निजी आयोजन था तथा इस्पात मंत्रालय ने इस आयोजन को अपना गैर-वित्तीय लोगो सहयोग प्रदान किया था।

(ख) और (ग): जी, हां। देश की क्रूड इस्पात उत्पादन क्षमता में वर्ष 2013-14 में 102.26 एमटी की तुलना में वर्ष 2022-23 में 161.29 एमटी तक की वृद्धि हुई है। भारत ने वर्ष 2018 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड इस्पात उत्पादक बन कर जापान को पीछे छोड़ दिया है। देश में वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022-23 तक के दौरान क्रूड इस्पात के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं तथा ये इस 10 वर्ष की अवधि के दौरान 5.0% की सीएजीआर को दर्शाते हैं:-

वर्ष	**क्रूड इस्पात का उत्पादन (एमटी में)**
2013-14	81.69
2014-15	88.98
2015-16	89.79
2016-17	97.94
2017-18	103.13
2018-19	110.92
2019-20	109.14
2020-21	103.54
2021-22	120.29
2022-23	127.20
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमटी= मिलियन टन	

(घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। नए संयंत्रों की स्थापना जैसे निर्णय बाजार पर आधारित होते हैं और ये इस्पात कंपनियों द्वारा प्रौद्यो-वाणिज्यिक व्यवहार्यताओं के आधार पर लिए जाते हैं।

*****